भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 457
मंगलवार, दिनांक 06 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति

457. श्री एस. निरंजन रेड्डी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए आरंभ किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के तहत आवंटित, संवितरित और प्रयुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में आज की तिथि तक हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हरित हाइड्रोजन केन्द्र के रूप में हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग का समर्थन करने में सक्षम क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

क) से ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मिशन का व्यापक उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक हब बनाना है।

निम्नलिखित घटकों को मिशन के हिस्से के रूप में घोषित किया गया है:

i. निर्यात एवं स्वदेशी उपयोग के जरिए मांग सृजन में सुविधा प्रदान करना;
ii. स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (साइट) कार्यक्रम, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजरों के निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल है;
iii. स्टील, मोबिलिटी, पोत परिवहन, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा अनुप्रयोगों, बायोमास से हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन भंडारण आदि के लिए पायलट परियोजनाएं;
iv. ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास;
v. अवसंरचना विकास के लिए सहायता;
vi. विनियमनों एवं मानकों की मजबूत व्यवस्था स्थापित करना;

vii. आर एंड डी के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी फ्रेमवर्क के माध्यम सहित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम;

viii. कौशल विकास कार्यक्रम; और

ix. जन-जागरुकता एवं पहुंच कार्यक्रम।

सरकार ने मिशन के सफल निष्पादन के लिए वित्त वर्ष 2029-30 तक 19744 करोड़ रु. का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया है।

भारत में स्ट्रेटजिक इंटरवेशन्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (साइट) योजना (मोड-1 ट्रांश-1) के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन सुविधा की स्थापना के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों के चयन हेतु निविदा को दिनांक 9 जनवरी, 2024 को कुल 4,12,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता हेतु 10 कंपनियों को आवंटित किया गया है।

भारत में साइट योजना (ट्रांश-1) के तहत इलेक्ट्रोलाइजर के लिए निर्माण क्षमता की स्थापना के लिए इलेक्ट्रोलाइजर निर्माता (ईएम) के चयन हेतु निविदा को दिनांक 12 जनवरी, 2024 को कुल 1500 मेगावाट प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए 8 कंपनियों को आवंटित किया गया है।

साइट मोड 2A (ग्रीन अमोनिया के लिए समेकन माडल) और मोड-2 बी (ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समेकन मॉडल) के लिए योजना दिशानिर्देश दिनांक 16 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।

शिपिंग क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 1 फरवरी, 2024 को योजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इन योजनाओं के तहत परियोजनाओं को एक बार अंतिम रूप देने के बाद, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक मुख्य घटक ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना है जो ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में हाइड्रोजन के बड़े स्तर पर उत्पादन और/या उपयोग में सहायक हो सकें।

मिशन के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में दो ग्रीन हाइड्रोजन केंद्रों की स्थापना की व्यवस्था है।

पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने तीन मुख्य बंदरगाहों जैसे कि दीनदयाल, पाराद्वीप और वी.ओ चिदंबरनार (तूतिकोरिन) बंदरगाह को हाइड्रोजन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए चिह्नित किया है।

*****